प्रिलिम्स फैक्ट्स (20 Feb, 2021)

drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/20-02-2021/print

प्रिलिम्स फैक्ट: 20 फरवरी, 2021

हैदराबाद: '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड'

हैदराबाद: '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड'

Hyderabad: '2020 Tree City of the World'

'आर्बर डे फाउंडेशन' और संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य और कृषि संगठन' (Food and Agriculture Organisation- FAO) द्वारा हैदराबाद शहर (तेलंगाना की राजधानी) को '2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड' के रूप में मान्यता दी गई है।

- हैदराबाद ने आर्बर डे फाउंडेशन के दूसरे वर्ष के कार्यक्रम में दुनिया के 51 अन्य शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है।
  इसमें अधिकांश शहर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के हैं।
- हैदराबाद यह मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है।

प्रमुख बिंदु:

'ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड' कार्यक्रम:

- यह ऐसे शहरों और कस्बों को इस प्रकार की मान्यता देने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जो यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिबद्ध हैं कि उनमें स्थित 'अर्बन फॉरेस्ट्स' और वृक्षों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाए एवं लगातार उनका प्रबंधन किया जाए।
- इटली के मंटोवा में वर्ष 2018 के 'वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट्स' में वैश्विक नेताओं ने 'मंटोवा ग्रीन सिटीज़ चैलेंज' और एक 'कॉल-फॉर-एक्शन' जारी किया। इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग 'ट्री प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम' में शामिल होना भी था।
  यह कार्यक्रम सामुदायिक आधार पर वृक्षों और वनों के प्रबंधन के लिये सबसे सफल दृष्टिकोण को साझा करने और उसे अपनाने हेतु एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर के शहरों को जोड़ने का प्रयास करता है।

- **शामिल संगठन:**
    यह कार्यक्रम 'आर्बर डे फाउंडेशन' और FAO की सहभागिता से चलाया जा रहा है।
- **मूल्यांकन हेतु 5 मानक:**
    इसके अंतर्गत एक शहर का मूल्यांकन पाँच मानकों पर किया जाता है - उत्तरदायित्त्व स्थापित करना, नियम निर्धारित करना, आपके पास क्या है यह जानना, संसाधनों का आवंटन करना।

हैदराबाद को मान्यता:

- हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे उसके 'हरिता हरम कार्यक्रम' और 'अर्बन फॉरेस्ट्स पार्कों' के माध्यम से शहरी वानिकी को बढ़ावा देने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिये चयनित किया गया है।
- **हरिता हरम कार्यक्रम**
    - **लक्ष्य:** यह राज्य के हरित क्षेत्र को कुल भौगोलिक क्षेत्र के वर्तमान 25.16 से 33% तक बढ़ाने के लिये तेलंगाना सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
    - **उद्देश्य:** इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नीकृत वनों का कायाकल्प करना, वनों को अतिक्रमण, आग, पशुचारण से बचाना और अधिक प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बहु-आयामी दृष्टिकोण से उनका संरक्षण किया जाना है।
    - **अर्बन फॉरेस्ट पार्क (UFP):** इस कार्यक्रम के तहत शहरों और आसपास के वनखंडों को UFP में विकसित किया गया है।
        ये अर्बन फॉरेस्ट पार्क न केवल स्वस्थ वातावरण प्रदान करेंगे, बल्कि राज्य में स्मार्ट, स्वच्छ, हरे, टिकाऊ और संपन्न शहरों के विकास में भी योगदान देंगे।

आर्बर डे फाउंडेशन

- आर्बर डे फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी संरक्षण और शिक्षा संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में नेब्रास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन रोसेनो द्वारा की गई थी।
- यह वृक्षारोपण के लिये समर्पित सबसे बड़ा गैर-लाभकारी सदस्य संगठन है।
- इसका उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और वर्तमान में हमारे सामने आने वाले कई वैश्विक समस्याओं जैसे- वायु की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, बदलती जलवायु, वनों की कटाई, गरीबी आदि के समाधान के रूप में वृक्षों की उपयोगिता सिद्ध करना।

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 20 फरवरी, 2021

छत्रपति शिवाजी महाराज

19 फरवरी, 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती मनाई गई। पुणे की जुन्नार तहसील के शिवनेरी किले में जन्मे शिवाजी, भोंसले-मराठा कबीले से थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने सैन्य संगठन, किला वास्तुकला, समाज और राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किये। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग करते हुए दुश्मनों के आक्रमण का सामना किया और अपनी सेना का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के समुद्री तटों की रक्षा के लिये छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही आधुनिक युग में भारत की पहली नौसेना का निर्माण किया था। मराठा नौसेना

ने जयगढ़, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और महाराष्ट्र के तट के साथ-साथ अन्य किलों की रक्षा की। वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा था और विभिन्न धर्मों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करते थे। राजा के तौर पर छत्रपति शिवाजी ने प्राचीन हिंदू राजनीतिक विचारों और न्यायिक प्रथाओं को पुनर्जीवित किया, साथ ही उन्होंने मराठी भाषा के उपयोग को भी सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने उन्हें 2,000 सैनिकों की एक सेना सौंपी थी, शिवाजी ने अपनी प्रशासनिक कुशलता द्वारा अपनी सैन्य क्षमता को 10,000 सैनिकों तक विस्तारित किया। औरंगज़ेब और उनके सेनापति ने शिवाजी की सैन्य कुशलता और रणनीति के कारण उन्हें 'माउंटेन रैट' के नाम से संबोधित किया था, क्योंकि वे मुगल सैनिकों पर हमला करते थे और वापस पहाड़ों पर लौट जाते थे।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस

प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन, उचित कार्य स्थिति और लैंगिक समानता आदि के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को और अधिक मज़बूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। वर्ष 2021 के लिये 'डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिये आह्वान' को विश्व सामाजिक न्याय दिवस का थीम चुना गया है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य देशों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और विकास के लिये आवश्यक सिद्धांत से है, जो न केवल अंत:देशीय समानता अपितु अंतर्देशीय समानता की परिस्थितियों से भी संबंधित है। सामाजिक न्याय की संकल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लिंग, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता आदि असमानताओं को समाप्त करना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ 'अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन' (ILO) के 'निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिये सामाजिक न्याय पर घोषणा' जैसे उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है। सामाजिक न्याय के 5 प्रमुख सिद्धांतों में शामिल हैं- संसाधनों तक पहुँच, न्याय संगतता, सहभागिता, विविधता और मानवाधिकार।

स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द इयर अवार्ड

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को 'स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द इयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया है। स्कॉच समूह द्वारा घोषित इस पुरस्कार के लिये चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना-स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित है। इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए स्कॉच समूह ने कहा कि 'वाईएसआर रैतु भरोसा केंद्र' जैसी योजनाओं ने ग्रामीण स्तर पर एक बेहतर मॉडल विकसित किया है। इसके अलावा कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध प्रतिक्रिया में सरकार द्वारा की गई पहलों के वांछनीय परिणाम देखने को मिले हैं। इस पुरस्कार के चयन के लिये स्कॉच समूह द्वारा आंध्र प्रदेश की कुल 123 परियोजनाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह सामने आया है कि राज्य सरकार ने शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बीते दो वर्षों में कई क्रांतिकारी और अभिनय उपाय किये हैं।

ननकाना साहिब नरसंहार

हाल ही में ननकाना साहिब नरसंहार अथवा शक ननकाना साहिब की 100वीं शताब्दी पर आयोजित समारोह की शुरुआत हो गई है। वर्ष 1920 में अस्तित्व में आते ही 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (SGPC) ने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 'महंतों' की निजी संपत्ति बन चुके गुरुद्वारों के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाना था। इस आंदोलन से

भयभीत 'महंतों' द्वारा फरवरी 1921 में लाहौर में 'सिख सनातन सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक निहत्थे सिख जत्थे ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करने और अहिंसक तरीके से गुरुद्वारे पर कब्ज़ा करने की योजना बनाई। वहीं दूसरी ओर गुरुद्वारे के अंदर हथियारों से लैस सशस्त्र सेना के साथ निहत्थे सिख जत्थे का मुकाबला करने के लिये तैयार थे। दोनों के बीच मुठभेड़ में 60 से अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई। 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (SGPC) का आरोप था कि इस नरसंहार में ब्रिटिश प्रशासन भी शामिल था। ननकाना साहिब गुरुद्वारा (जिसे गुरुद्वारा जन्म स्थान भी कहा जाता है) उस जगह पर बनाया गया है जहाँ सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था।